*126. [The questioner (Shri Abu Asim Azmi and Shri Amar Singh) were absent. For Answer *vide* pages 28 - 29. *Infra*]

Potable and ground water crisis in Rajasthan

*127. SHRI K.B. KRISHNA MURTHY: Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government have received any proposal from the Government of Rajasthan regarding the potable and ground water crisis faced by the State last year;

(b) if so, the details thereof;

(c) the amount of grant extended to the State Government against the said proposals; and

(d) whether Government are willing to extend concessions granted under Accelerated Rural Water Supply Programme in drought hit areas of the State?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI ANNASAHEB M.K. PATIL): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) Yes, Sir. Government of Rajasthan had furnished a Contingency Plan for mitigating drinking water scarcity situation in all 32 districts of the State declared as drought affected during 2002-03.

(c) An amount of Rs. 1200 lakh has been released to the Government of Rajasthan during 2002-2003 for meeting requirement of drinking water in the rural areas in the wake of drought conditions out of 5% of Accelerated Rural Water Supply Programme (ARWSP) fund earmarked for meeting contingencies arising out of natural calamities and other emergent situations. Under the normal Accelerated Rural Water Supply Programme, Rs. 17625.30 lakh have been released. Under the Desert Development Programme area (DDP) component of Accelerated Rural Water Supply Programme, Rs. 4770.66 lakh have also been released.

(d) From the current financial year 2002-2003, 5% of the allocation under ARWSP has been set apart for meeting the emergent situations such as drought and other natural calamities in the country.

श्री मूल चंद मीणा: सभापति महोदय, राजस्थान सरकार की ओर से पीने के पानी के लिए केन्द्र सरकार को योजना प्रस्तावित की गई थी। लेकिन केन्द्र सरकार की ओर से वर्ष 2002-2003 के दौरान 1,200 लाख रुपए रिलीज किए गए। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार की योजना कितने रुपये की थी? आपने राजस्थान सरकार की योजना के अनुसार पैसा न देकर जो तात्कालिक योजना थी, उसका हवाला इस प्रश्न के उत्तर में दे दिया है। इसलिए राजस्थान सरकार की जो मांग थी, उस मांग के अनुसार आपने तात्कालिक पैसा रिलीज करने में कमी क्यों की, इसके कारण बताइए।

श्री सभापति: क्या आप बता सकते हैं कि राजस्थान सरकार ने कितनी मांग की थी?

श्री मूल चंद मीणा: यह मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

श्री सभापति: आप ही बता दीजिए क्योंकि आप सवाल पूछ रहे हैं।

श्री अन्नासाहेब एम॰ के॰ पाटील: महोदय, राजस्थान सरकार ने 205 करोड़ रुपए की मांग की थी। राजस्थान सरकार ने वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए 15 करोड़, rejuvenation and deeping of tube-wells के लिए 45 करोड़ और पेयजल के लिए 145 करोड़ रुपये की मांग की थी। इस तरह कुल मिलाकर उन्होंने 205 करोड़ रुपये की मांग की थी। इसके लिए हमें ARWSP से जो निधि उपलब्ध होती है,उसमें से हमने राजस्थान सरकार को 12 करोड़ रुपया दिया है और out of 47 lakh tonns which have been released for the whole country, उसमें से 10 लाख टन अनाज हमने राजस्थान को दिया है।

श्री मूल चंद मीणा: इसका अनाज से कोई संबंध नहीं है। यह तो पानी का सवाल है ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: पानी का उन्होंने बता दिया है।

श्री मूल चंद मीणा: महोदय, राज्य सरकार 205 करोड़ रुपए मांगे और केन्द्र सरकार केवल 12 करोड़ रुपए दे और उसके बाद आप कहते हैं कि हम अकाल में सहायता करना चाहते हैं। कैसे आप सहायता करेंगे?

श्री अन्नासाहेब एम॰ के॰ पाटील: देखिए, राजस्थान सरकार ने पानी के ट्रांसपोर्टेशन के लिए 15 करोड़ रुपए मांगे थे। उनकी ऐप्लीकेशन मेरे पास आई है। राजस्थान सरकार की जो मांग थी उसमें पेयजल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए उन्होंने 15 करोड़ रुपए मांगे थे ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: इनका प्रश्न सीधा है कि पेयजल के लिए राजस्थान सरकार ने कितनी मांग की थी, वह बता दीजिए।

श्री अन्नासाहेब एम॰ के॰ पाटील: महोदय, पेयजल के लिए उन्होंने 205 करोड़ रुपए मांगे थे।

श्री मूल चंद मीणा: महोदय, 205 करोड़ रुपए में से इन्होंने 12 करोड़ रुपए दिए हैं। मंत्री महोदय, राजस्थान में पिछले 40 साल से लगातार अकाल पड़ा हुआ है और इस समय 41,000 गांव, 4 करोड़ जनसंख्या, 5 करोड़ पशुधन इससे प्रभावित है। उनके पीने के पानी की व्यवस्था के लिए आप केवल 12 करोड़ रुपए दे रहे हैं। जबकि राज्य सरकार ने 205 करोड़ रुपए मांगे हैं। कैसे आप आम लोगों की सहायता करेंगे? कैसे आप उनको पानी उपलब्ध कराएंगे? क्या इस बारे में आपकी कोई विशेष योजना है?

श्री सभापति: आप इस बारे में कुछ बता सकते हैं क्या?

श्री अन्नासाहेब एम॰ के॰ पाटील: महोदय, जो कैलेमिटी के लिए फंड होता है वह केवल रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से नहीं होता है, वह दूसरे डिपार्टमेंटस से भी होता है। हमने अपने डिमार्टमेंट से 12 करोड़ रुपए दिए हैं। इसके अलावा उन्हें CRF से और कुछ मिला होगा ...(व्यवधान)...

श्री नीलोत्पल बसु: अगर यह तैयारी करके सरकार सदन में आएगी तो सवाल पूछने का क्या मतलब है? आप इसे बंद कर दीजिए। इस तमाशे की कोई जरूरत नहीं है ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: यह जो पानी के लिए है और पानी या अकाल के लिए जो सहायता दी जाती है वह डिफ्रेंट नॉर्म्स से दी जाती है। सी॰आर॰एफ॰ के अंदर दी जाती है, एन॰ सी॰ एफ॰ में दी जाती है। वाटर की अलग स्कीम है, उसमें दी जाती है। वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए अलग स्कीम है, उसमें दी जाती है। ...(व्यवधान)...

श्री नीलोत्पल बसु: सर, क्षमा कीजिए, आप जो एक्सप्लेन कर रहे हैं वह मंत्री जी को एक्सप्लेन करना चाहिए। हमारे सवाल का फिर कोई मतलब नहीं है।

श्री अन्नासाहेब एम॰ के॰ पाटील: सर, रेग्यूलर पेयजल की जो योजनाएं हैं ए॰ आर॰ डब्ल्यू॰ एस॰ पी॰ उसके अंदर हमने राजस्थान सरकार को 176 करोड़ रुपए पेयजल के लिए दिया है। और ड्रोट कंडीशन के लिए हमने 47 करोड़ 70 लाख दिया है और पी॰ एम॰ जी॰ वाई॰ के माध्यम से हमने 10 करोड़ 61 लाख दिया है। अभी जो हमने 12 करोड़ का बताया वह केलेमिटी के लिए है।

श्री सभापति: आप यह पहले ही बतला देते।

श्री मूल चंद मीणा: सभापति महोदय, यह मानवता से संबंधित है, यह अकाल से संबंधित है ..(व्यवधान)...

डा॰ अबरार अहमद: माननीय सभापति, जहां सूखे में पेयजल के लिए क्या दिया गया है, सवाल में यह पूछा गया है, तो माननीय मंत्री जी जवाब के अंदर जो 176 करोड़ की बात कर रहे हैं उसका अकाल से कोई ताल्लुक नहीं है। 47 करोड़ की जो बात उत्तर में कही है उसका अकाल से

कोई ताल्लुक नहीं है। राजस्थान में 65 प्रतिशत वर्षा कम हुई है इस साल। चार साल लगातार अकाल पड़ने के बाद 65 प्रतिशत कम वर्षा होने के बावजूद जो 12 करोड़ रुपए दिया गया है वह तो ऊंट के मुंह में जीरा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि कठिन समय राजस्थान में अब आ रहा है। तो वह कितना पैसा राजस्थान को पेयजल के लिए जून-जुलाई में देने जा रहे हैं?

श्री अन्नासाहेब एम० के० पाटील: सर, यह तो मिनिस्ट्रियल कमेटी तय करती है जो मिनिस्टर वर्किंग ग्रुप है उसके पास यह प्रस्ताव जाएगा।

डा० प्रभा ठाकुर: जो पेयजल योजनाएं चलाई जा रही हैं ..(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: It will not go on record (*Interruptions*) Question No. 128.

डा० प्रभा ठाकुर:*

Intermediate Jet trainer developed by HAL

*128. SHRIMATI N.P. DURGA: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether the Intermediate Jet Trainer developed by the Hindustan Aeronautics Limited has been tested;

(b) if so, will it fill IAF's technical gap in the training of pilots; and

(c) by when will they be inducted into IAF?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

The Intermediate Jet Trainer (IJT) is presently undergoing ground tests, including engine ground run, leading to its first flight.

Indian Air Force (IAF) are presently using Kiran trainers to train their pilots, These aircrafts have technologies of the sixties and seventies and are approaching their fatigue life. The IJT is being developed for State II training of the pilots. It will have state-of-the-art Avionics, Display Systems, Fuel Efficient Engine and increased armament capabilities, incorporating latest technologies. This will improve pilots' training effectiveness with better speed, range, endurance and advanced avionics systems.

* Not recorded